नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की नवीं बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुये। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने का खाका पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, किसानों का सशक्तिकरण, एम.एस.एम.ई. योजनाओं को विशेष प्रोत्साहन देने की योजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। राजस्थान को रिन्युएबल एनर्जी निर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनाने की योजनाओं पर भी प्रदेश सरकार विशेष ध्यान दे रही हैं।

भाजपा मुख्यालय में भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली प्र.मंत्री मोदी ने

केन्द्र में तीसरी बार प्र.मंत्री बनने के बाद यह पहला मौका है जब मोदी इस तरह की बैठक कर रहे हैं

- **इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा भी शामिल हुये। बैठक की शुरुआत में प्र.मंत्री मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अभिनंदन किया गया।**
- **बैठक के दूसरे दिन सभी भाजपाई मु.मंत्री अपने राज्यों में चल रही विकास योजना की अप-टू-डेट रिपोर्ट पेश करेंगे तथा प्र.मंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा भी करने वाले हैं।**

नई दिल्ली, 27 जुलाई। नीति आयोग गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में शामिल न होकर विपक्ष ने विकसित भारत के मोदी सरकार के लक्ष्य में असहयोग का बिगुल भले ही फूंक दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डबल इंजन सरकार के सहारे अपने संकल्प रथ को गति देने के लिए तैयार हैं। शनिवार को भाजपा मुख्यालय में शुरू हुई भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की दो दिवसीय बैठक में पार्टी का जोर इसी पर है।

हर राज्य की ओर से विकास का खाका पेश किया जाना है। बैठक को प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे। केंद्र में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने के बाद यह पहला अवसर है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं।

शनिवार शाम को प्र.मंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री का तीसरी बार लगातार विजय के लिए अभिनंदन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक के उद्देश्य पर विचार रखा।

बताया गया है कि पार्टी की ओर से सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से पहले ही कह दिया गया था कि अपने-अपने राज्यों में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की अद्यतन स्थिति, उनकी सफलता और लागू करने में आ रही बाधा पर रिपोर्ट सहित प्रदेश सरकारों ने सभी वर्गों के कल्याण को लक्षित करते हुए जो भी योजनाएं और नवाचार शुरू किए हों उनका ब्योरा लेकर आएं। सभी मु.मंत्री और डिप्टी मु.मंत्री इस तैयारी के साथ पहुंचे हैं।

गौरतलब है कि इस तरह की बैठक कर एक दूसरे की अच्छी योजनाओं का अनुसरण करने को कहा जाता है। ऐसी ही एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे अब केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में क्रियान्वित किया गया है। बैठक में अपने नवाचार साझा करने का क्रम शनिवार को शुरू हो गया और रविवार को भी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अपने राज्यों के कार्यकलापों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मध्य प्रदेश से डॉ. मोहन यादव, राजस्थान से भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी, गुजरात से भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय, हरियाणा से नायब सिंह सैनी, असम से हिमंत बिस्वा सरमा पहुंचे।

ओडिशा से मु.मंत्री मोहन चरण माझी, त्रिपुरा से माणिक साहा, अरुणाचल प्रदेश से पेमा खांडू, गोवा से प्रमोद सावंत, मणिपुर से बिरेन सिंह, बिहार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और महाराष्ट्र से डिप्टी मु.मंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। संभावना है कि रविवार को सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मन की बात को भी एक साथ सुनें।

विकसित भारत 2047 की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप

नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की नवीं बैठक में शामिल हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री

- **मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी और बताया कि राज्य सरकार में डेढ़ लाख करोड़ रूपए के एम.ओ.यू. किए हैं।**
- **मुख्यमंत्री ने ई.आर.सी.पी. और यमुना जल समझौते के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि इससे राज्य के 21 जिलों की जनता को पानी मिलेगा।**
- **मुख्यमंत्री ने विकसित राजस्थान को पूर्ण विकसित बनाने के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं सड़क निर्माण के क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी भी दी।**

नई दिल्ली, 27 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउन्सिल की नवीं बैठक में शिरकत करते हुए विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप काउन्सिल के सामने रखा। शर्मा ने बैठक में कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 10 संकल्प लिए हैं जिसमें आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की इकोनमी को 350 बिलियन डॉलर बनाने, बुनियादी सुविधाएं, शहरी ग्रामीण एवं क्षेत्रीय तथा मानव संसाधनों का विकास, किसानों का सशक्तिकरण, एम.एस.एम.एस.ई. को प्रोत्साहन देना तथा विरासत संरक्षण के साथ-साथ सबके लिए स्वास्थ्य, सुशासन जैसे महत्वपूर्ण घटकों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही बिजली के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम उठाए हैं। हमनें एन.टी.पी.सी., एन.टी.पी.पी. ग्रीन, कोल इंडिया, एन.एल.सी और आर.ई.सी. जैसे केंद्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 50 हजार करोड़ के एम.ओ.यू. संपादित किए हैं। जिसके तहत 32 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2950 मेगावाट की सोलर परियोजना हेतु भूमि आवंटित कर दी है तथा पीएम कुसुम योजना के तहत 7 महीने की अल्पावधि में 4386 मेगावाट क्षमता के प्रोडक्ट्स हेतु लैटर ऑफ इन्टैन्ट जारी किए हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने ई.आर.सी.पी. परियोजना तथा यमुना जल समझौते के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ई.आर.सी.पी. परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित कर राज्य के 21 जिलों के 3 करोड़ 25 लाख लोगों का सपना साकार हुआ है तथा हमने जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपए व्यय करके 25 लाख घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु बजट में 27 हजार 660 करोड रुपए का प्रावधान किया है जो राज्य बजट का 8.26 प्रतिशत है। राज्य में फरवरी, 2024 से "मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना" प्रारंभ कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए 134 राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राईमरी कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया है तथा 402 पी.एम.श्री. विद्यालयों में वर्चुअल ऑनलाइन लैब स्थापित किया जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में राज्य सरकार द्वारा पिछले 7 माह में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें 2,750 किलोमीटर लंबाई के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण, राज्य के हर जिले में मातृ वन बनाने, किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़कर 8,000 करने तथा इस समयावधि में 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान करने के साथ-साथ राज्य में "वन स्टेट-वन इलेक्शन" व्यवस्था लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा और पोंग बांध को पूर्ण क्षमता तक भरने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है ताकि राज्य को उसके हिस्से का पानी आसानी से मिल सके। उन्होंने जल जीवन मिशन की अवधि मार्च 2027 तक बढ़ाई जाने का आग्रह भी किया। उन्होंने राज्य को आवंटित 2 लाख सोलर पंप के लक्ष्य को बढ़ाकर 6 लाख किए जाने का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया।

राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि परियोजना की बढ़ी हुई लागत 72 हजार 937 करोड़ रुपए का अनुमोदन शीघ्र किया जाए ताकि रिफायनरी के काम को जल्द पूर्ण किया जा सके। शर्मा ने राजस्थान के विकास में पर्यटन की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है इसलिए धार्मिक स्थलों के विकास हेतु केंद्रीय सहयोग अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग को जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर विकसित किया जाए।

राहुल ने मोची को भेजा गिफ्ट

- **राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर में जिस मोची की गुमटी पर उससे मिलने गये थे, शनिवार को उन्होंने उस मोची के लिए जूते सिलने वाली मशीन भिजवा दी।**

नई दिल्ली, 27 जुलाई। सुलतानपुर में अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए राहुल गांधी की चर्चा इस समय शहर से लेकर गांव तक हो रही है। शुक्रवार को राहुल गांधी एक मुकदमे में एम.पी.-एम.एल.ए. कोर्ट में बयान दर्ज कराने आए थे। दिल्ली वापस लौटते समय वे गुप्तारगंज कस्बे के विधायकनगर में अचानक मोची चैतराम की दुकान पर रुक गए। उन्होंने मोची से जूता बनाने की विधि के बारे में पूछा और उनके साथ कोल्ड ड्रिंक पी। थोड़ी देर बातचीत की और आगे बढ़ गए। शनिवार को उन्होंने दिल्ली से अपनी टीम भेजकर मोची को जूता बनाने की मशीन भेज दी। बदले में मोची चैतराम ने भी राहुल गांधी को रिटर्न गिफ्ट दिया। मोची ने उपहार में चमड़े के दो जूते भिजवाए।

शनिवार को मोची चैतराम के पास दिन में करीब 11 बजे फोन आया कि आपको राहुल ने जूता बनाने की मशीन भिजवाई है।

पुतिन से हो चुकी बात अब यूक्रेन के प्रधानमंत्री से बात करने जायेंगे मोदी

यूक्रेन-रूस युद्ध को खत्म करने पर बातचीत के लिए प्र.मंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं

- **प्रधानमंत्री मोदी की, लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी जीत के बाद प्रधानमंत्री ज़ैलैंस्की ने उन्हें बधाई दी थी और यूक्रेन की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया था।**

नई दिल्ली, 27 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद पहली बार अगले महीने कीव की यात्रा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्र.मंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जा सकते हैं। आपको बता दें कि करीब एक महीना पहले इटली में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी।

इटली में दोनों नेताओं को मिलते समय गले मिलते देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी जीत के बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें बधाई दी थी और यूक्रेन की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया था।

प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यात्रा से इसलिए भी युद्ध की समाप्ति के आसार बन रहे हैं क्योंकि वह रूस की यात्रा के ठीक बाद यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले जेलेंस्की ने प्र.मंत्री मोदी से मध्यस्थता करने की अपील की थी।

इससे पहले सितंबर 2022 में उज्बेक शहर समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्र.मंत्री मोदी ने कहा था, "आज का युग युद्ध का नहीं है।" उन्होंने पुतिन से यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए कहा। उनके संदेश को दुनिया का तमाम नेताओं से प्रशंसा मिली।

इस साल मार्च में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ एक फोन कॉल में प्र.मंत्री मोदी ने भारत-यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने इस दौरान संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आ ान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हरसंभव प्रयास करता रहेगा।

युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत का मानना रहा है कि इसे केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत किसी भी शांति प्रयास में योगदान देने के लिए तैयार है।

दिल्ली: कोचिंग...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बेसमेंट में पानी भर गया है और कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि शाम को भारी बारिश के कारण सड़क पर जलभराव हो गया था। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं कि पूरा बेसमेंट कैसे भर गया।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बेसमेंट में बहुत तेजी से पानी भर गया और कुछ लोग बेसमेंट के अंदर फंस गए। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की बचाव टीमें यहां मौजूद हैं। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। अब तक दो स्टूडेंट्स की बॉडी बरामद हुई है।

भाजपा अध्यक्ष जे.पी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के आम चुनावों में मोदी अल्पमत में आ गये थे, उस समय आर.एस.एस. की योजना उनके स्थान पर किसी और नेता बनाने की थी।

लेकिन मोदी ने भाजपा या भाजपा संसदीय दल की मीटिंग ही नहीं बुलाई। इसके स्थान पर, उन्होंने एन.डी.ए. की मीटिंग बुलाई तथा एन.डी.ए. सदस्यों से अपना समर्थन करवा लिया।

यह बात स्वयं में कितनी महत्वपूर्ण है कि भाजपा संसदीय दल का कोई पत्र राष्ट्रपति के पास नहीं गया था तथा राष्ट्रपति ने भी इस प्रकार का कोई पत्र माँगना उचित नहीं समझा।

अब यह लड़ाई पूरी तरह खुले में आ गई है। मोहन भागवत और नरेन्द्र मोदी में इस समय खूली अनबन है।

यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन टिका रहता है और कौन बाहर कर दिया जाता है।

ऐसी सम्भावना है कि अगर संघर्ष की स्थिति बनती है तो आर.एस.एस. मूल के सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी।

ऐसी स्थिति में, जब मोदी-शाह योगी आदित्यनाथ से छुटकारा पाने के लिये पूरी-पूरी कोशिश एवं मेहनत कर रहे हैं तब योगी-प्रकरण क्या रूप लेता है, उससे यह स्पष्ट संकेत मिल जायेगा कि भाजपा की राजनीति किस दिशा में जा रही है।

अनंतनाग में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिन्हा ने दुखद सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सिन्हा ने कहा, आज अनंतनाग के डकसुम में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियों के नुकसान के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ हैं। मैंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती सहित कई राजनीतिक नेताओं ने भी इस दुखद दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है।

जम्मू-कश्मीर में एक माह में नवां आतंकी हमला

शनिवार सुबह ही आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरु हो गई, जिसमें सुरक्षाबलों के तीन जवान घायल हो गये तथा एक जवान शहीद हो गया

- **सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मारने में कामयाबी हासिल की है। संदेह जताया जा रहा है कि यह आतंकी पाकिस्तानी सेना का एस.एस.जी कमाण्डो हो सकता है।**

श्रीनगर, 27 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के एल.ओ.सी. के पास वाले जिले कुपवाड़ा में आज सुबह सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है इसके साथ ही मेजर समेत तीन और जवानों के घायल होने की खबर है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी के भी ढ़ेर होने की खबरें सामने आई है। घायल सैनिकों घटनास्थल से निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुपवाड़ा में यह पिछले एक महीने में चौथी आतंक की घटना है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जवान मुच्छल सेक्टर के कुमकाडी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना को कुमकाडी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सैनिकों ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया था। सेना के द्वारा और सैनिकों को भेजकर इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। रक्षा सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में पाकिस्तानी बैट(बॉर्डर एक्शन टीम) टीम का हाथ है। हमले में शामिल बैट टीम में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो सहित पाकिस्तान की नियमित सेना के सैनिक होने का संदेह है जो आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं।

बुधवार को कुपवाडा जिले में ही सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक आतंकी मारा गया था। एक सैनिक भी घायल हो गया था। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर सेना की तरफ से बताया गया था कि आतंकियों की मौजूदगी के संबंध में खबर मिली थी।

नीति आयोग प्रकरण में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में भाग ले रही थीं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक से एकमात्र ममता बनर्जी ही थीं, जिन्होंने नीति आयोग की बैठक में भाग लिया था जबकि अन्य ने यह आरोप लगाकर बैठक का बहिष्कार किया था कि केन्द्र ने बजट में उनकी मांगों की अनदेखी की है। विपक्ष की राजनीति में खुद को अलग-थलग पाकर ममता बनर्जी बैठक बीच में ही बायकॉट का नाटक किया।

प्रैस इन्फॉमेशन ब्यूरो, जिसने ममता बनर्जी के दावे का फैक्ट चैक किया था, ने बयान जारी किया कि ममता बनर्जी का दावा "भ्रामक" है। ब्यूरो ने कहा "ऑफिशियल क्लॉक" बता रही है कि वे अपने निर्धारित समय से ज्यादा देर बोली। यहां तक कि उनको टाइम खत्म होने की सूचना देने वाली घंटी भी नहीं बजाई गई। ममता बनर्जी का दावा था कि उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि वरिष्ठ नेता होने के नाते उनसे अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। सत्य तो यह हे कि ममता बनर्जी विपक्ष से अलग-थलग पड़ गई हैं, अन्य नेताओं को ज्यादा तवज्जो मिल रही है।

इसके अलावा विपक्ष का सारा फोकस राहुल गांधी पर है। इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों की राजनीति नहीं समझ पाने के कारण नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होने वाली वही एकमात्र विपक्षी मुख्यमंत्री थीं, बाकी सब एन.डी.ए के सहयोगी दल थे। वह अक्सर अपनी वरिष्ठता का ढोल पीटती रहती हैं और यह बताती हैं कि वे कई बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। प्रैस की सुर्खियों में आने के लिए नियमित रूप से वे ऐसी हरकते करती रहती हैं।

राजस्थान से...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रुप से डॉग मीट खाया जाता है, वहां भी मांस के लिए कुत्ते को मारना प्रतिबंधित है। बेंगलुरू पुलिस ने कहा कि राजस्थान से आने वाले मीट को मटन कहकर बेचा जा रहा है, जबकि वास्तव में, वो मटन नहीं है। यदि लैब परीक्षणों में इस बात की पुष्टी हो गई कि यह कुत्ते का मांस है तो आरोपियों के खिलाफ सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

जे.डी.ए. सचिव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बताया गया कि परिवादी पी.आर.एन. का सफल आवंटी है, लेकिन उसे पी.आर.एन. में भूखंड का कब्जा नहीं दिया गया, जिस पर उसने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। आयोग ने 26 जुलाई 2013 को फैसला देते हुए जे.डी.ए. पर 2500 रुपए हर्जाना लगाते हुए निर्देश दिया कि वह परिवादी को पी.आर.एन. में ही भूखंड दे। जे.डी.ए. ने आदेश की पालना करने के बजाय, इसे राज्य उपभोक्ता आयोग और बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी, लेकिन दोनों ही जगह पर जे.डी.ए. हारा और जिला उपभोक्ता आयोग का फैसला बरकरार रखा गया। इस पर जे.डी.ए. ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी गत 13 फरवरी को जे.डी.ए. की एस.एल.पी. खारिज कर दी। इस पर परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चल रहे अवमानना मामले में आदेश की पालना करवाने का आग्रह किया, जिस पर आयोग ने जे.डी.ए. सचिव के गिरफ्तारी वारंट व जे.डी.सी. के जमानती वारंट जारी कर उन्हें तलब किया है।

ममता बनर्जी ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दोनों से मुलाकात की थी। मुख्य बात यह है कि बनर्जी ने कई बार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से भिन्न रुख अपनाया था, परन्तु मोटे तौर पर वह भाजपा का विरोध करने वाली ताकतों के साथ प्रतिबद्ध रही हैं। मनोज झा ने यह भी कहा कि "भाजपा यदि यह सोचती है तो यह उसकी गलतफहमी है कि विपक्षी समूह में समन्वय की कमी है। समन्वय है या नहीं है यह एक बिलकुल ही अलग बात है। परन्तु, सार यह है कि हब सब एकजुट हैं और एकसाथ खड़े हैं।"

महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह से कश्मीर मसले पर खास अपील की

महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह से कहा, आप कश्मीर और पी.ओ.के मसले पर शांति स्थापित करने के लिए दोंनो देशों के 20-20 प्रतिनिधियों की एक समिति बनाइये

- **महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह से कहा कि राष्ट्र हित में वे अपना अहंकार त्याग दें और लाइन ऑफ कन्ट्रोल (एल.ओ.सी.) के दोनों ओर के लोगों के प्रतिनिधियों की बैठक कराएं, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था।**

श्रीनगर, 27 जुलाई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लाने के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक सुझाव दिया है। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के लोगों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने का आव्हान किया। पीडीपी के 25वें स्थापना दिवस समारोह में महबूबा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रत्येक पक्ष के 20 प्रतिनिधियों की एक समिति बनाने की अपील की।

उन्होंने कहा, "अमित शाह कहते हैं कि वह कश्मीर (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) वापस लाएंगे, जबकि आप हम मुसलमानों से कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ।" पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, "हालांकि मेरा आपसे एक अनुरोध है। जब तक आप उस हिस्से को वापस नहीं लाते, तब तक इस कश्मीर और उस कश्मीर के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाइए तथा हमें साथ लाइए। हम साल में दो बार एक साथ बैठेंगे और हमारे सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे।"

उन्होंने शाह से कहा कि राष्ट्र के हित में वह अपना अहंकार त्याग दें और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के दोनों ओर के लोगों के प्रतिनिधियों की बैठक कराएं जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल के दौरान किया था। महबूबा ने कहा, "क्या आपमें हिम्मत है अमित शाह साहब? आप कहते रहते हैं कि आप उस कश्मीर को वापस लाएंगे। वह कश्मीर बहुत दूर है, उनके 20 प्रतिनिधि और हमारे 20 प्रतिनिधि लाइए और हमें एकसाथ बैठने दीजिए।" उन्होंने सवाल किया, "क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपमें ऐसा करने की हिम्मत है? क्या आपमें वाजपेयी की तरह देशभक्ति है कि आप जम्मू कश्मीर के लिए अपने अहंकार का त्याग कर दें?" महबूबा ने देशभर की जेलों में बंद कश्मीरी युवाओं को रिहा करने का भी आव्हान किया।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908